

सम्पादकीय

आतंक की चिंतित करती
चुनौती, कन्हैयालाल-उमेश
कोल्हे की हत्या को हल्के में
लेने वालों के लिए चेतावनी

नुपुर शर्मा विवाद के बाद दो हत्याओं ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। अब उनसे संबंधित आरोपण च्यालाल्य में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे और राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या से संबंधित आरोपणों से स्पष्ट हो जाता है कि ये तात्कालिक गुस्से में की गई हत्याएं नहीं थीं। हत्यारे और हत्या की साजिश रचने वाले कठुरपंथी इस्लामी विचारधारा वाले समूहों से जुड़े थे। कोल्हे की हत्या में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआइए ने पाया कि सभी आरोपित तल्लीयी जमात से जुड़े थे तो कन्हैयालाल के हत्यारे दावत-ए-इस्लामी से। ये आतंकी माझ्युल की तरह काम कर रहे थे। कन्हैयालाल की हत्या में दो पाकिस्तानियों का नाम भी आरोपणत्र में हैं। वास्तव में ये आरोपणत्र उन लोगों के लिए चेतावनी जैसे होने चाहिए, जो ऐसे जघन्य हत्याकांडों पर भी राजनीति कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह कहकर इसे हल्का करने प्रयास किया कि नुपुर की पैंगंबर साहब पर टिप्पणी से गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा किया होगा। हालांकि सामान्य अवस्था में इस तरह कोई गला नहीं काटता। यह वही करने की हिम्मत जुटाएगा, जिसमें यह भाव भरा गया हो कि इस्लाम के विरोध को सहन करना मजहब विरोधी आचरण है तथा ऐसे विरोधियों की हत्या ही मजहब की सेवा है। ऐसा वही कर सकते हैं, जो पूरजोर तरीके से यह नारा लगाते हैं कि 'गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा।' इन दानों हत्याओं की अभी तक हुई जांच के आधार पर प्रस्तुत आरोपणों ने इस बात को सच साबित किया है। अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या 21 जून तथा उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या 28 जून को हुई थी। कन्हैयालाल की हत्या उसकी दुकान में दिनदहाड़े घुसकर की गई और हत्यारों ने उसका वीडियो भी जारी किया। वीडियो ने लोगों को आतंकित कर दिया था। वहीं, उमेश कोल्हे जब अपनी दुकान से लौट रहे थे तो दो बाइक सवारों ने उनका पीछा किया, उन्हें रोका और धारदार हथियारों से गला काट दिया। उस समय अनुसान लगाना कठिन था कि यह वार्किंग नुपुर शर्मा विवाद से जुड़ी हत्या है। बाद में हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ मामला खुला। दोनों जगह पहले राज्य पुलिस ने जांच आरंभ की, लेकिन इसमें कठुर इस्लामी आतंकवाद की भूमिका सामने आने के साथ मामले एनआइए को सौंप दिए गए। एनआइए के आरोपणत्र में लिखा है कि ये कठुरपंथी ही थे और भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किए जा रहे आडियो-वीडियो संदेशों से प्रेरणा लेते थे। उदयपुर मामले से जुड़े आरोपणत्र में हत्यारों रियाज अंसारी और गौस मोहम्मद के अलागा जिन नौ लोगों को आरोपित बनाया गया, उनमें दो सलमान और अबू इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं। दोनों कई गांठसंप्रय ग्रप के एडमिन थे, जिनमें भड़काऊ मैसेज आते थे। रियाज और गौस उससे जुड़े थे। दोनों मामलों की आरंभिक जांच से जितने तथ्य सामने आए, उससे अनुसान लगा गया था कि ये कोई सामान्य मामले नहीं। आखिर कन्हैयालाल का दोष क्या था? उसके बेटे ने मोबाइल फोन पर एक पोस्ट शेयर किया, जो वायरल हो गया था। उसे जब धमकियां मिलीं, तो उसने माफी भी मांगी, लेकिन धमकी आती रही और उसकी हत्या हो गई। इसी तरह उमेश कोल्हे ने नुपुर के समर्थन का एक पोस्ट साझा किया था। आरोपितों में से एक यूसुफ खान उमेश कोल्हे का दोस्त था। उसी ने उमेश के पोस्ट को वायरल किया तथा हत्या की साजिश रची। इसके लिए बैठकें हुईं। उनमें तल्लीगी जमात के विचार रखे और तय किया गया कि उमेश कोल्हे नबी का अपराधी है और उसकी हत्या आवश्यक है। एनआइए ने स्पष्ट कहा है कि यह केवल एक साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि अमरावती और अन्य क्षेत्रों में लोगों को आतंकित करने के लिए तल्लीगी जमात के कठुरपंथियों की ओर से रची गई एक सुनियोजित आपराधिक साजिश थी। एनआइए की मानें तो इन कठुरपंथियों का सोच था कि ऐसा करने से लोगों में डर पैदा होगा। आरोपणत्र के अनुसार जांच में स्पष्ट हो गया कि तल्लीगी जमात के कठुरपंथियों ने उमेश कोल्हे की हत्या विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए की थी। तल्लीगी जमात एक सुन्नी संगठन है।

भारत की भूमिका के विस्तार का समय, नववर्ष में वैश्विक कूटनीति के शिखर पर भी होगा 'नया भारत'

इस साल का अब सप्ताह भर शेष रह गया है तो इस साल का पड़ताल और नवर्ष से उम्मीदों का आकलन बहुत स्वाभाविक है। इस साल महामारी से लगभग मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन वर्ष बीतते-बीतते चोन से कुछ खतरनाक संकेत सामने आने लगे हैं। फरवरी में यूक्रेन और

रुस के बाच छिड़ युद्ध के भा वपात 0.8 प्रतशत पर आ गया ह। यह आकलन वर्ष 2004-05 से कोराना काल वाले 2020-21 के बीच का है। नि-संदेह कोरोना काल में गरीबी घटाने के सरकारी प्रयासों को झटका लगा, किंतु आइप्पाएफ की रिपोर्ट संकेत करती है कि तालिबंदी से रोजगार छिन जाने और विस्थापित होकर गांव-देहात पहुंचे कामगार निराश्रित नहीं थे। सरकारी सहायता ने भी उन्हें बड़ा सहारा दिया। यह

तक शात पड़ने के काइ आसार नहीं दिख रहे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया में राजनीतिक एवं आर्थिक समीकरण बिंगाड़ दिए। दिसंबर 2022 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए भारत अच्छी तरह से तैयार है। यह इसीलिए संभव हुआ, क्योंकि बीते आठ वर्षों में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' सहित तमाम नीतियां फलदायी सिद्ध हुई हैं। क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के स्तर पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना अनुकूल आर्थिक नीतियों का ही परिणाम सहजता से कहा जा सकता है कि घरेलू स्तर पर अपनी नींव सुढ़ाने के साथ 'नया भारत' नववर्ष में वैश्विक कूटनीति के शिखर पर भी होगा। सितंबर 2023 तक भू-राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा से संबंधित संगठन 'शंघाई सहयोग संगठन' और शक्तिशाली आर्थिक समूह 'जी-20' की नवंबर 2023 तक भारत अध्यक्षता करेगा। यह हमारे देश की ताकत है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी 'यह युद्ध का दौर नहीं' वैश्विक विर्माश के केंद्र में रही।

घातक सिद्ध होती आगे निकलने की होड़, अब आत्महत्याओं के लिए कुख्यात हो रहा कोटा शहर

छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं से जुड़ी नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट हाल में आई है। इसके अनुसार 2022 में छात्रों ने सबसे अधिक आत्महत्याएं की हैं। 2021 के मुकाबले छात्रों की आत्महत्याएँ में इस साल 4.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2016 से 2021 के बीच छात्र आत्महत्या के मामलों में की तैयारियों के साथ-साथ अब आत्महत्याओं का हब भी बन रहा है। कोटा में जिस प्रकार बच्चों में आत्महत्या करने का ग्राफ बढ़ रहा है उससे अब कोटा की कोचिंग व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पिछले पांच वर्षों में कोटा में 77 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। कोटा पुलिस से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि 2011 में छह, 2012 में 11, किशोर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। उनका सप्ताह उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने और उसको उत्तीर्ण करने से जुड़ा होता है। उनकी कोचिंग पर प्रत्येक अभिभावक हर वर्ष ४०० सतन ढाई से तीन लाख रुपये खर्च करते हैं। कई मामलों में अभिभावक कोचिंग की फीस बैंक या अन्य जगहों से ऋण लेकर भी चुकाते हैं। इसलिए

ओर जो छात्र कोचिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनके साथ बहुत डॉन-टपट करते हैं। देखने में आया है कि कभी-कभी अध्यापक ऐसे कमजोर बच्चों का बैच भी अलग कर देते हैं। कई बार कोचिंग संचालक एवं शिक्षक ऐसे कमजोर बच्चों के अभिभावकों को केंद्र पर बुलाकर उनकी कमियों को सबके सामने उजागर करते हैं और उन्हें में भी कठिनाई महसूस करते हैं। साथ ही प्रतियागिता की तीव्र होड़ी से उपजने वाली निराशा को कम करने में परिवार और कोचिंग संस्थानों से संवाद का अभाव उहै अपने जीवन से हारने को मजबूत करता है। रही-सही कसर बाकी प्रतियोगी छात्रों की असफलता पूरा कर देती है। असल में इन प्रतियागियों परीक्षाओं में कोचिंग के बाबजूद

इन बच्चों को इस दबाव और तनाव से मुक्त करने के लिए जरूरी यह है कि ये कोचिंग संस्थान अपने यहां एक मनोचिकित्सक के साथ-साथ एक वाटांसलर और फिजियोलाजिस्ट की भी भर्ती करें। साथ ही इन बच्चों के अभिभावकों की भी काउंसिलिंग करें, जिससे वे अपने बच्चों की समय-समय पर कार्य निष्पादन क्षमता को जान सकें। इसके साथ-साथ इन बच्चों को लगातार कोचिंग के बीच में कुछ समय उनको मुक्त करते हुए योगाभ्यास इत्यादि से जोड़ना भी बहुत जरूरी है। छात्रों की लगातार चिकित्सा जांच के साथ उनके मनोरंजन की व्यवस्था और उनके कोचिंग शुल्क में भी किस्तों की व्यवस्था करने से बच्चों के मानसिक दबाव में कमी आने की संभावना है। वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा के इस दौर में व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो इशैक्षिक संवेदनाओं को निगल रही है। रातों-रात लक्ष्य प्राप्ति की होइ ने तो शैक्षिक मूल्यों को ही ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों की शैक्षिक क्षमता का समय रहते आकलन करें। यह इन कोचिंग संस्थानों की भी जिम्मेदारी है कि वे खुद कोचिंग की इस व्यवसायी संस्कृति से बाहर आकर इन छात्रों को भी इस उपभोक्ता बाजार के चंगूल से बाहर निकालें और सच्चे अभिभावक की भूमिका अदा करें। तभी ये बच्चे कोचिंग के दबाव से बाहर निकलेंगे और उनके सुरक्षित और सुखद भविष्य का सपना साकार हो सकेगा।



ऐसा लगता है जैसे कोटा परीक्षा कोटा में हर वर्ष तकरीबन डेढ़ लाख उन पर अधिक ध्यान देते हैं। दूसरी और नए परिवेश को आत्मसात करने भी किया था, परंतु हाल-फिलहाल साकार हो सकेगा।

वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार भारत, प्रासंगिक हो रहा 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का विचार

जी-20 इन दिनों चर्चा में है। दिसंबर में ही भारत ने इस वैशिक समूह की कमान संभाली है। अध्यक्षता संभालने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के मंत्र का आहान किया। उन्होंने इसके पीछे की संकल्पना का भी उल्लेख किया, 'कोई विकसित दुनिया और कोई आर्थिक राष्ट्रवाद जैसी दुर्दार्ता चूनौतियां इस राह में कुछ बड़े अवरोध के रूप में दिखती हैं। साथ ही, रूस-यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी का काला साया, जलवाया आपदाएं और भूमंडलीकरण से प्रत्येक स्तर पर चिंचलन से उपर्याप्त बेलगम महार्ग, ब्याज दरों में तेजी का सिलसिला और निरंतर बढ़ती

परिपास ले जाने की बिन मांगी सलाह
देते हैं। कहने की जरूरत नहीं
भय का यह मनोविज्ञान इन
चर्चों को निराशा से भर देता है।
उपर्युक्त परिवर्गों से दूर रहकर कोचिंग
करने वाले ये छात्र एक अनजान
और नए परिवेश को आत्मसात करने

सफलता का प्रतिशत लगभग 10
प्रतिशत के आसपास ही रहता है।
केंद्र सरकार ने कोटा में इन
प्रतियोगी छात्रों में बढ़ती आमत्यत्वा
की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के
लिए छह सदस्यीय समिति का गठन
भी किया था, परंतु हाल-फिलहाल

नरम मुदास्फीति, निम्न व्याज दरें
और सस्ते श्रम, ऊर्जा, धारुओं और
खनिजों की आपूर्ति से लाभान्वित
हुई। जब आर्थिक वृद्धि और लोगों
की बेहतरी पर खतरा मंडरा रहा
हो तो पारंपरिक संवादों और
परिचर्याओं की सार्थकता संदिग्ध
होने लगती है। एक ऐसे दौर में
जब दुनिया कुछ इसी प्रकार की

आघात नहीं पहुँचना चाहिए। इसके बजाय उसे आर्थिकी से जुड़े जोखिमों को दूर कर उसे सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे में समय की आवश्यकता है कि सामाजिक असंतोष और आर्थिक गतिरोध को रोकते हुए लोगों, पूँजी और वस्तुओं एवं सेवाओं की मुक्त आवाजाही के



तीसरी दुनिया नहीं' और 'एक विश्व कहने का यही आशय है कि समूह मानवता 'एक परिवार' के रूप साझा समृद्धि करे और अशक्त प्रभु को 'एक भविष्य' के लिए सहायता देकर सशक्त बनाया जाए। ये सभी बातें तो प्रशंसनीय हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक प्रकृति वह देखते हुए सबल उनके फलदायक होने का लेवर जुड़ा है भूराजनीतिक हलचल, दृष्टिगण्ठ राजनीति, उद्घंड तानाशाही और

आर्थिक दुश्खारियां स्थिति को और बिगाइने वाली हैं। संप्रति विश्व सम्पुदाय के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजनीतिक विमर्श भी आर्थिक वृद्धि के प्रति उदासीनता को दर्शने वाला है। यहां कुछ तथ्यों की पड़ताल उपयोगी होगी। पिछली सदी के नौवें दशक के मध्य से 2007 के बीच की अवधि को 'व्यापक समभाव' का दौर माना जाता है, जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं वृद्धि की ओर प्रभावी भूमिका निभाई। डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत साकार होता दिखने के साथ ही आर्थिक वृद्धि पर भी सार्वभौमिक ध्यान केंद्रित था। दुर्भाग्यवश, ये पहलू अब कमजोर पड़ रहे हैं और दुनिया भर में आर्थिक मुश्किलें एवं असमानता बढ़ती दिख रही हैं। विकसित देशों में कामकाजी आबादी, विस्थापन और महिलाओं की व्यापक भागीदारी के साथ ही तकनीकी उन्नयन ने कुल कारक उत्पादकता

परिविक के देएक भारगयामूल हमहैं 3को मिलराष्ट्र

जननांकीय स्थिति प्रतिकूल हो रही है, विस्थापन को रोका जा रहा है और महिलाओं की भागीदारी चरम पर पहुंच गई है। कोविड ने काम को लेकर हिचक बढ़ाई है। तकनीकी सुधार अपनी एक सीमा में ही यापादन कर पा रहे हैं। स्परण रहे कि विकासशील देशों को आउटसोर्सिंग, पंजी की पर्याप्त प्रवाह और तकनीकी विकास की साझेदारी से लाभ पहुंचा। वहीं, समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था भराजनीतिक शांति,

थतियों से दो-चार हो, तब सेत विश्व और तीसरी दुनिया गों को 'एक पृथ्वी, एक परिवार, परिष्ठ' के सूत्र में परिणे गाल का विचार और प्रासंगिक हो है। ऐसे में सभी बैठकों के भी यही बात होनी चाहिए कि सभी एक ही नाव पर तैर रहे र नैया पार लगाने पर सभी सहयोग का बराबर लाभ गा। स्पष्ट है कि आर्थिक गण से आर्थिकी के स्तंभों को

